

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तराखण्ड।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 22 नवम्बर, 2016

विषय:- मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिकाओं एवं सिविल अपीलों में प्रतिवाद आदेश निर्गत किया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में रिट याचिकायें एवं सिविल अपीलें मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित हो रही हैं, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट पदनाम से प्रत्यर्थी हैं और उनमें प्रतिवाद के आदेश अपेक्षित हैं।

2- सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए और ऐसे प्रकरणों में त्वरित सुनवाई को सुगम बनाये जाने के उद्देश्य से मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित उन रिट याचिकाओं एवं सिविल अपीलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट पदनाम से प्रत्यर्थी हैं, प्रतिवाद करने एवं प्रतिवाद आदेश निर्गत करने हेतु राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया जाता है, परन्तु इस प्रकार के आदेशों को पारित करने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासन के अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से न्याय विभाग को मासिक संकलन सूचना उपलब्ध कराते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। जिन प्रकरणों में जिला मजिस्ट्रेट पदनाम से प्रत्यर्थी न हो अथवा जिन प्रकरणों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवाद न किये जाने का विनिश्चय किया जाये, उन प्रकरणों को विधि परामर्शी निदेशिका के प्रावधानों के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट शासन के अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से न्याय विभाग को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिन मामलों में जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रतिशपथ प्रस्तुत किया गया है, उनका पूर्ण विवरण भी प्रतिशपथ प्रस्तुत किये जाने से एक सप्ताह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट शासन के अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से न्याय विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

3- अतः मुझे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में उपर्युक्त वर्णित लम्बित विधिक कार्यवाहियों में प्रतिवाद आदेश में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिये अपने स्तर से उक्त व्यवस्था के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

सं- 482 (1)/XXXVI(1)/2016-251/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 6- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव।